Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 18, Issue No. 4, July-2021, ISSN 2230-7540

महिलाओं की राजनीतिक में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति

Nishat Arshi[1]*, Dr. Deepa Kushwah[2]

[1] Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.

[2] Professor, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.

सार - पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता का विचार तेजी से बदल रहा है, क्योंकि 2013 तक, ब्रिटिश संसद के सभी सदस्यों में से एक तिहाई महिलाएं हैं। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास का एक नया भाव आया है और उनकी खुद की छवि में सुधार हुआ है। हमारे समाज में महिलाओं के बहुत सारे अधिकार हैं, और कई लोगों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है कि उनके साथ उचित व्यवहार किया जाए। दुर्भाग्य से, महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई बनाने के लिए एक विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि कभी-कभी महिलाओं को वह सम्मान नहीं मिलता जिसकी वे हकदार होती हैं।

----------------------------------x----------------------------------

परिचय

प्रागैतिहासिक काल से सिंधु सभ्यता के समय तक सभ्यता और संस्कृति का विकास होता रहा। बाद में, लोगों के विभिन्न समूह - राजपूतों की तरह - इस क्षेत्र में अपने स्वयं के स्वतंत्र राज्य बनाने लगे। भारत की स्वतंत्रता से पहले, इस क्षेत्र को केवल राजस्थान के नाम से जाना जाता था। कर्नल जेम्स टोडज्य राजस्थान से हैं, जिसे राजाओं का घर कहा जाता है। रतन एक नाम है जो “प्रांत“ के लिए संस्कृत शब्द से लिया गया है। आजादी से पहले राजस्थान 18 रियासतों में बंटा हुआ था। बाद में, दो क्षेत्रों को राज्य में जोड़ा गया। आजादी के बाद राजस्थान के वर्तमान राज्य के गठन की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी हुई।

सरकार हमेशा भारत को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम कर रही है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद! भारत सरकार लोगों के विभिन्न समूहों से बनी है, जिसमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोग शामिल हैं। भारत एक ऐसा देश है जो कई अलग-अलग संस्कृतियों और धर्मों से बना है, इसलिए सरकार को ऐसे निर्णय लेने की कोशिश करनी चाहिए जिससे सभी को लाभ हो। सरकार कानून पारित करके लोगों की जरूरत में मदद करती है। उदाहरण के लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सहायता और सहायता प्रदान करके उनकी मदद करता है। सरकार ऐसा करने का एक तरीका पंचायती राज अध्यादेश (1948 में पारित) के माध्यम से गांवों में लोगों के साथ काम कर रही है। सरकार लोगों का एक समूह है जो कानून बनाने, देश को संगठित करने और यह तय करने के प्रभारी हैं कि सभी के लिए सबसे अच्छा क्या है।

1957 में, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, इस पर सिफारिशों के साथ आने के लिए लोगों के एक समूह का गठन किया गया था। यह प्रणाली 1959 में पारित की गई थी और ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तरों पर पंचायतों की स्थापना की प्रक्रिया को गति प्रदान की गई थी। ग्राम पंचायत चुनाव पहली बार राजस्थान में 1959 में पेश किए गए थे। इस कानून ने उन पंचायतों को बनाने में मदद की जहां पहले कोई नहीं था, और विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को कैसे शामिल किया जाए, इस पर सिफारिशें करने के लिए एक समिति भी बनाई।

1960 में राजस्थान में पहला औपचारिक चुनाव हुआ। 1963 में चीनी आक्रमण के बाद पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। उन्होंने पाया कि संस्थाएँ अच्छी तरह से काम कर रही थीं, और उनमें शामिल लोग खुश

www.ignited.in

थे। समूह ने **1964** में राजस्थान सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

अध्ययन में पाया गया कि पुनर्वास योजनाएं राजस्थान में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती हैं। इसका मतलब यह है कि जो लोग भारत या विदेश के दूसरे हिस्सों में नए घरों में स्थानांतरित हो गए हैं, उनके पास अपने घरों में रहने वालों की तुलना में बेहतर जीवन हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुनर्वास योजनाएँ उन लोगों की मदद करती हैं जिन्हें सफल होने के लिए आवश्यक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए स्थानांतरित किया जाता है। कार्यक्रम जो उपलब्ध संसाधनों का सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करते हैं और विकलांग लोगों के जीवन में सुधार लाने वाले विकास कार्यक्रम दोनों ही बहुत सफल रहे हैं। हालाँकि, अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इन कार्यक्रमों में सुधार किया जा सकता है। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्पादन और विकास कार्यक्रमों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण है। अध्ययन में विकास कार्यों में जनता की रुचि और पंचायती राज संस्थाओं के भीतर संसाधनों के एकीकरण की स्थिति को भी देखा गया। अंत में, अध्ययन ने पंचायती राज संस्थाओं के काम के रुझानों और उन तरीकों को देखा, जिनसे वे बदलती जरूरतों के अनुकूल हो रहे हैं।

अध्ययन दल ने तेरह बार मुलाकात की और दो प्रश्नावली तैयार की। उन्होंने विभिन्न राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था में काम करने वाले लोगों को सामग्री भेजी और व्यवस्था कैसे काम करती है, इसके बारे में अधिक जानने के लिए इन राज्यों का दौरा भी किया। समिति ने पाया कि पंचायती राज को कई अलग-अलग तरीकों से लागू किया जा रहा है, और कुछ महत्वपूर्ण रुझान हैं जिनका वह अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करना चाहेगी।

पंचायती राज प्रणाली ने क्षेत्रों में कुछ समस्याएं पैदा की हैं, क्योंकि लोग अपने कर्तव्यों की तुलना में अपने अधिकारों को अधिक महत्व दे रहे हैं। विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के बीच और सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच इस बात को लेकर कुछ असहमति है कि वे एक साथ कितनी अच्छी तरह काम करते हैं। कर्मचारियों की भर्ती में देरी हुई है, और सेवाओं में अनुशासन प्रणाली बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर पाई है। लेखांकन मामलों में सुधार की भी आवश्यकता है, और जिस तरह से हस्तांतरित योजनाओं को लागू किया जा रहा है। अधिक जन सहयोग की आवश्यकता है।

समिति ने कहा कि किलेबंदी हटाने के लिए हमें सरकारी अधिकारियों और समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच अच्छे संबंध रखने की जरूरत है। उन्होंने इसे हासिल करने में मदद के लिए कुछ सुझाव दिए।

जनप्रतिनिधियों को अपना कार्य करते समय हमेशा सिद्धांतों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। इन सिद्धांतों में एक जनप्रतिनिधि के लक्ष्यों को निर्धारित करना और फिर जनता को इस लक्ष्य के बारे में सूचित करना शामिल है। अधिकारियों को सावधानी बरतनी चाहिए कि सलाह देते समय कोई व्यक्तिगत पक्षपात न हो, और इसके बजाय उन्हें अनुभव के आधार पर अपनी सलाह देनी चाहिए। हम इस परामर्श में समुदाय के लिए सबसे अच्छा करेंगे। हम कानूनों और विनियमों का पालन करेंगे, और यह सुनिश्चित करेंगे कि परामर्श सभी के लिए सर्वोत्तम क्या है, इस पर आधारित है।

सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके अधिकारी और प्रतिनिधि अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वे जानते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, ताकि गलतफहमियों और मनमुटाव से बचा जा सके।

यदि आप सुनते हैं कि कोई अपने मित्र से नाराज है, तो आपको समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। उच्च स्तर के अधिकारी मदद कर सकते हैं।

अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अपने काम की जिम्मेदारियों को जानना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इससे उनके बीच अच्छे संबंध बनाने में मदद मिलेगी।

प्रतिनिधियों को पता होना चाहिए कि पुलिस को सलाह देने का अधिकार है, और चुने हुए प्रतिनिधियों को भी यह अधिकार है कि अगर वे चाहें तो उस सलाह को अनदेखा कर सकते हैं।

अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों को अपने निजी स्वार्थों को परे रखकर जनता के हित के लिए अपना काम करने का प्रयास करना चाहिए।

कुछ अल्पकालिक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों एक दूसरे के साथ मधुर और सौहार्दपूर्ण रहने के महत्व से अवगत हो सकें।

क्रिया विधि

यह शोध एक विशिष्ट क्षेत्र में एक आदिवासी समुदाय में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन के बारे में है।

लिंग के आधार पर:-

पुरुषों और महिलाओं के बीच शारीरिक अंतर सार्वभौमिक है और इसमें विभिन्न चीजें शामिल हैं जैसे उनके जननांगों का आकार और उनके शरीर में अन्य अंतर। पुरुषों और महिलाओं के बीच मूलभूत अंतर यह है कि पुरुषों के लिंग होते हैं और महिलाओं के योनि होते हैं। अन्य अंतर भी हैं, जैसे उनके शरीर की लंबाई और चैड़ाई और उनकी छाती पर वे स्थान जहां वे दूध का उत्पादन करते हैं। ये अंतर हमेशा से रहे हैं, और ये समय के साथ बदलते रहते हैं।

तालिका संख्या 1 लिंग के आधार पर वर्गीकरण

क्रम संख्या	उत्तरदाताओं की संख्या		योग
	पुरूष	महिला	
1	150	150	**300**
योग	150	150	**300**

तालिका 3.1 में लोगों को 300 लोगों में से चुना गया था। 150 पुरुषों और 150 महिलाओं को विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि से चुना गया था।

पारिवारिक संरचनाः-

परिवार लोगों का एक समूह है जो विवाह, रक्त या गोद लेने से संबंधित हैं। परिवार एक घर में एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत और संवाद करके एक साझा संस्कृति बनाते हैं।'

संयुक्त परिवारः-

संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं और आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। वे पारिवारिक कर्तव्य से बंधे हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं और एक इकाई के रूप में मिलकर काम करते हैं।

एकाकी परिवारः-

एक परिवार जिसमें केवल एक विवाहित युगल और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, प्राथमिक परिवार कहलाते हैं। इस प्रकार का परिवार कई देशों में आम है।

अन्य परिवारः-

अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के परिवार पाये जाते हैं। कुछ परिवारों में दो माता-पिता होते हैं, कुछ के माता-पिता एक होते हैं और कुछ परिवारों में माता-पिता नहीं होते हैं। कुछ परिवार एकल परिवार होते हैं, जो दो माता-पिता वाले परिवार होते हैं। कुछ परिवार परित्यक्त परिवार होते हैं, जो ऐसे परिवार होते हैं जहाँ एक या दोनों माता-पिता ने परिवार को छोड़ दिया होता है। कुछ परिवार विधुर परिवार होते हैं, जो ऐसे परिवार होते हैं जिनमें एक या दोनों माता-पिता की मृत्यु हो जाती है। अंत में, कुछ परिवार विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चों से बने होते हैं। परिवार संरचना की जानकारी अध्ययन क्षेत्र के लोगों से प्राप्त हुई है।

तालिका संख्या 2 पारिवारिक संरचना

क्र.सं.	पारिवारिक संरचना	उत्तरदाताओं की संख्या		योग
		पुरूष(प्रतिशत)	महिला(प्रतिशत)	(प्रतिशत)
1	संयुक्त	60(40.00)	56(36.67)	116(38.67)
2	एकांकी	75(50.00)	78(52.67)	153(51.00)
3	अन्य	15(10.00)	16(10.66)	31(10.33)
	योग	150(100.00)	150(100.00)	300(100.00)

सर्वेक्षण किए गए 300 लोगों के आंकड़ों के अनुसार, अध्ययन क्षेत्र में 38.67ः परिवार संयुक्त परिवार हैं, अध्ययन में कुल 100 लोग हैं। उनमें से 51ः एकल परिवार वाले परिवार हैं, जो कि घरों का सबसे आम प्रकार है। हालांकि, जो घर विधुर या विधवाओं के हैं, उनकी जनसंख्या का 10.33ः हिस्सा है, जो कि उच्चतम प्रतिशत है। यह जानकारी सर्वेक्षण किए गए 300 लोगों के डेटा पर आधारित है।

आयु संरचनाः-

गांव में बुजुर्ग महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे समुदाय के नेता हैं। यह ग्रामीण स्तर पर विशेष रूप से सच है, जहां उम्र को किसी भी अन्य कारक की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। आदिवासी समाज में रहने वाले वृद्ध लोगों की सामाजिक, व्यावसायिक और राजनीतिक गतिशीलता के बारे में अधिक जानने के लिए एक जाँच की गई।

तालिका संख्या 3 आयु संरचना

क्र.सं.	आयु वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या		योग
		पुरुष(प्रतिशत)	महिला(प्रतिशत)	(प्रतिशत)
1	21–30	20(13.33)	15(10.00)	35(11.67)
2	31–40	40(26.67)	45(30.00)	85(28.33)
3	41–50	54(36.00)	60(40.00)	114(38.00)
4	51–60	25(16.67)	21(14.00)	46(15.33)
5	61 – ऊपर	11(07.33)	09(06.00)	20(06.67)
	योग	150(100.00)	150(100.00)	300(100.00)

तालिका 3.3 से पता चलता है कि 21-30 के आयु वर्ग में बहुत से लोग हैं, और ये लोग अध्ययन किए गए लोगों की कुल संख्या का 11.7ः बनाते हैं। इसके बाद, तालिका 3.3 से पता चलता है कि 31-40 आयु वर्ग के लोगों का प्रतिशत बहुत अधिक है- 28.3ः। हालाँकि, 41-50 आयु वर्ग के लोगों का प्रतिशत अभी भी 38.0ः अधिक है। इसका अर्थ है कि इस आयु वर्ग में बहुत से लोग हैं, और उनका प्रतिशत किसी भी अन्य आयु वर्ग से बड़ा है।

वैवाहिक स्थितिः-

अध्ययन जनजातीय समाजों में सामाजिक गतिशीलता और राजनीतिक जागरूकता पर विचार कर रहा है। यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर उनकी वैवाहिक स्थिति क्या है।

लोगों को उनकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर चार समूहों में विभाजित किया जा सकता हैः विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा। इस जानकारी के आधार पर, इन अलग-अलग समूहों के लोगों के साथ अलग-अलग चीजें होती हैं।

तालिका संख्या 4 वैवाहिक स्थिति

क्र.सं.	वैवाहिक स्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या		योग
		पुरूष(प्रतिशत)	महिला(प्रतिशत)	(प्रतिशत)
1	विवाहित	138(92.00)	142(94.67)	180(93.33)
2	अविवाहित	05(3.33)	–	05(01.67)
3	विधुर/विधवा	05(3.33)	08(5.33)	13(04.33)
4	तलाकशुदा	02(1.34)	–	02(00.67)
	योग	150(100.00)	150(100.00)	300(100.00)

तालिका के अनुसार, 93.33ः उत्तरदाता विवाहित हैं, जिसमें 138 पुरुष और 142 महिला उत्तरदाता शामिल हैं। अविवाहित उत्तरदाताओं का प्रतिशत 1.67ः है। इसमें 5 पुरूष उत्तरदाता विधुर तथा 8 महिला उत्तरदाता विधुर हैं। अध्ययन में पाया गया कि क्षेत्र के अधिकांश लोग तलाकशुदा या परित्यक्त हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अध्ययन में केवल पुरुष शामिल थे, इसलिए महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है।

शिक्षा का स्तरः- तालिका इस अध्ययन में लोगों की शैक्षिक स्थिति को दर्शाती है। "शिक्षा" लेबल वाला कॉलम इस अध्ययन में लोगों की शिक्षा के स्तर को दर्शाता है। "देश" लेबल वाला कॉलम दिखाता है कि इस अध्ययन में लोगों का जन्म कहाँ हुआ था। "जनजाति" लेबल वाले कॉलम से पता चलता है कि इस अध्ययन में लोग किस जनजाति के हैं। "लिंग" कॉलम दिखाता है कि इस अध्ययन में कितने पुरुष और महिलाएं हैं। "आयु" कॉलम दिखाता है कि इस अध्ययन में शामिल लोगों की उम्र कितनी है।

तालिका संख्या 5 शिक्षा का स्तर

www.ignited.in

क्र. सं.	शिक्षा का स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या		योग
		पुरूष(प्रतिशत)	महिला(प्रतिशत)	(प्रतिशत)
1	उच्च प्राथमिक (6–8)	–	10(06.67)	10(03.33)
2	माध्यमिक (9–10)	20(13.33)	25(16.67)	45(15.00)
3	उच्च माध्यमिक (11–12)	34(22.67)	44(29.33)	78(26.00)
4	स्नातक	47(31.33)	38(25.33)	85(28.33)
5	स्नात्कोत्तर	31(20.67)	19(12.67)	50(16.67)
6	व्यावसायिक / डिग्री–शिक्षा	18(12.00)	14(09.33)	32(10.67)
	योग	150(100.00)	150(100.00)	300(100.00)

अध्ययन में पाया गया कि यद्यपि महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुषों ने माध्यमिक विद्यालय पूरा किया है, दोनों लिंगों में समान प्रतिशत वाले लोग हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा स्तर, जैसे कि स्नातक की डिग्री पूरी की है। यह देश के अधिकांश क्षेत्रों से अलग है, जहां उच्च प्रतिशत लोगों के पास केवल माध्यमिक शिक्षा है।

मकान का स्वरूपः-

भूमि का वह भाग जहाँ लोग रहते हैं, मानव निवास कहलाता है। इसमें वे स्थान शामिल हैं जहाँ लोग अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियाँ करते हैं। हमने मीणा जनजाति के लोगों से उनके आवास की व्यवस्था के बारे में जानने के लिए बात की। नीचे दी गई तालिका में उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के घरों को दिखाया गया है।

तालिका संख्या 6 मकान का स्वरूप

क्र. सं.	मकान का स्वरूप	उत्तरदाताओं की संख्या		योग
		पुरूष(प्रतिशत)	महिला(प्रतिशत)	(प्रतिशत)
1	कच्चे मकान	40(26.67)	35(23.33)	75(25.00)
2	पक्के मकान	60(40.00)	55(36.67)	115(38.33)
3	मिश्रित मकान	35(23.33)	45(30.00)	80(26.67)
4	किराये के मकान	15(10.00)	15(10.00)	30(10.00)
	योग	150(100.00)	150(100.00)	300(100.00)

महिला नेतृत्व दायित्व

भारतीय संसद के 73वें सत्र में एक ऐसे संशोधन को मंजूरी दी गई जिससे पंचायती व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी आसान हो जाएगी। यह प्रणाली भारत में एक प्रकार की स्थानीय सरकार है, और यह महत्वपूर्ण है कि इसमें महिलाओं की वास्तविक भूमिका हो क्योंकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालाँकि, महिलाओं के लिए इस प्रणाली में प्रभावी ढंग से भाग लेना अभी भी मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग महिलाओं के अधिकारों और पंचायती व्यवस्था में उनकी भागीदारी के महत्व के बारे में जागरूक नहीं हैं। हालाँकि, जैसे-जैसे अधिक महिलाएं इसके बारे में जागरूक होती हैं, व्यवस्था में उनकी भूमिका बदलने लगती है।

भारत सरकार ने फैसला किया कि सार्वजनिक जीवन में अधिक महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने एक संविधान बनाया जो इसकी अनुमति देता है। इसलिए, 1992 में यह सुनिश्चित करने के लिए 73वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस संशोधन अधिनियम ने भारतीय गांवों के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई, जिससे महिलाओं को अपने समुदायों का नेतृत्व करने का मौका मिला।

उपसंहार

इसलिए, मेरा उद्देश्य ग्रामीण समाज में राजनीति में महिलाओं की स्थिति, भागीदारी और भूमिका का वास्तविक मूल्यांकन प्रदान करना है, विशेष रूप से 2000 के जिला पंचायत चुनावों के संदर्भ में। ऐसा करने के लिए, मैंने महिलाओं की वास्तविक भागीदारी पर कई शोध साक्षात्कार लिए, गाँवों में जाकर अनगिनत महिलाओं से चर्चा की, उनकी कार्यशैली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जहां शीतलपुर प्रखंड के भागीपुर गांव की प्रधान सुश्री शारदा देवी का कहना है कि "पुरुष अहंकार के कारण ही महिलाओं को आगे बढ़ने में कठिनाई होती है. पुरुष नहीं चाहते कि महिलाएं सामाजिक कार्यों में उनके साथ आगे बढ़ें। प्रखंड शीतलपुर. अहमदाबाद ग्राम प्रधान सुश्री निर्मला तोमर ने इस अवसर पर खुले तौर पर कहाः "सोए हुए बुजुर्गों को जगाना होगा, उन्हें घर की दहलीज पार करके अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा।"

मैं यह वर्णन करना चाहता हूं कि 2000 के जिला पंचायत चुनावों के आधार पर महिलाएं ग्रामीण समाज में अपनी राजनीतिक भागीदारी के संदर्भ में क्या उम्मीद कर सकती

हैं। ऐसा करने के लिए, मैंने महिलाओं की वास्तविक भागीदारी पर कई शोध साक्षात्कार लिए, गाँवों में जाकर अनगिनत महिलाओं से चर्चा की, उनकी कार्यशैली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जहां शीतलपुर प्रखंड के भागीपुर गांव की प्रधान सुश्री शारदा देवी का कहना है कि "पुरुष अहंकार के कारण ही महिलाओं को आगे बढ़ने में कठिनाई होती है. पुरुष नहीं चाहते कि महिलाएं सामाजिक कार्यों में उनके साथ आगे बढ़ें। प्रखंड शीतलपुर. अहमदाबाद ग्राम प्रधान सुश्री निर्मला तोमर ने इस अवसर पर खुले तौर पर कहाः "सोए हुए बुजुर्गों को जगाना होगा, उन्हें घर की दहलीज पार करके अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा।"

ग्रामीण समाज पिछड़ रहा है क्योंकि कई महिलाएं अनपढ़ हैं और उन्हें नहीं पता कि उनके गांव के लिए सबसे अच्छा क्या है। जो महिलाएं शिक्षित हैं और बहुत बुद्धिमान हैं, वे गांव को आगे बढ़ने में मदद करने की कुंजी हैं। महिलाएं जानकारी साझा करने के लिए बैठकें आयोजित कर सकती हैं और चर्चा कर सकती हैं कि गांव को क्या काम करना चाहिए। अधिकारियों को अपने द्वारा खर्च किए जा रहे पैसे से सावधान रहने की जरूरत है ताकि यह गांव को बेहतर बनाने में मदद कर सके। गाँव की प्रगति में पुरुषों और महिलाओं की अलग-अलग भूमिकाएँ होती हैं, और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि

बीजू,एम.आर., डायनामिक्स आॅफ न्यू प ंचायत राज सिस्टम, नई दिल्ली, कनिष्क पब्लिषर्स,1997

शेलूचामी, एस., पंचायती राज इन्स्टीट्यूषंस, न्यू देहली, मित्तल पब्लिकेषंस, 2004

बनर्जी, सोनाली, सोषियल बैक ग्राउण्ड आॅफ पंचायत लीडर्स इन वेस्ट बंगाल, कोलकाता, दास गुप्ता एण्ड क0, 2002

बाबेल, डाॅ0 बंसतीलाल, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाऐं, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2001

बन्धोपध्याय,डी मुखर्जी, एमपावरिंग वीमन पंचायत मेम्बर्स हेण्ड बुक

अभितावा फोर मास्टर ट्रेनर्स यूजिंग पार्टिसिपेटरी अप्रोच, न्यू देहली, कन्सेप्ट पब्लिषिंग कम्पनी, 2006

बघेल,इन्दू, दलित वीमन इन पंचायती राज न्यू देहली,जनादा प्रकाषन,2009

बीजू, एम.आर., दि सेन्ट्रलाइजेषनः एन इण्डियन एक्सपिरियन्स जयपुर,नेषनल पब्लिकेषंस,2007

उमेष, सी. साहू, डवलपमेन्ट, न्यू देहली, रावत पब्लिकेषंस 2008

चैधरी, डी.एस., इमर्जिंग रूरल लीडरषिप इन इण्डियन स्टेट्स, नई दिल्ली, मंथन पब्लिकेषंस, 1981

चन्देल, चतुर्वेदी, डाॅ0 धर्मवीर, नत्थीलाल, भारत में पंचायती राज सिद्धान्त एवं व्यवहार, आविष्कार पब्लिषर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयुपर, 2010

चैधरी,विमलेष, महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बना नही हैः पंचायती राज व्यवस्था, राजस्थान विकास,अप्रेल-जुलाई, 2001(संयुक्तांक)

जैन, एस.पी., इण्डिया, हैदराबाद, नेषनल इन्स्टीट्यूट आॅफ रूरल डबलप मैन्ट,1995

चक्रवर्ती के., भट्टाचार्य,लीडरषिप फंक्षंस एण्ड पंचायत राज, जयपुर रावत पब्लिकेष ंस,1993

चतुर्वेदी, टी.एन. पंचायती राज, न्यू देहली,इण्डियन इन्स्टीटयूट आॅफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेषन,1981

चाहर,एस.एस.गवर्नेन्स एट ग्रास रूट लेवल इन इण्डिया न्यू देहलीः कनिष्का, 2005.

दरसानकर, ए.आर., लीडर षिप इन पंचायत राज,जयपुर पंचषील प्रकाषन,1979

दास, प्रभाकर, इमर्जिंग पैटर्न आॅफ लीडरषिप इन ट्रायबल इण्डिया,नई दिल्ली, मानव पब्लिकेषंस,1994

दुबे, एम.पी. और मुन्नी डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेषन और पंचायती राज इन इण्डिया, न्यू देहली,अनामिका पब्लिसर्ष,2002

देपाल, शषि, राजस्थान का बदलता सामाजिक स्वरूप, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर 2012

Corresponding Author

Nishat Arshi*

Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.